

प्रेषक,

शैलेश बगौली,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,

हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-04

देहरादून दिनांक 28 जुलाई, 2017

विषय-वित्तीय वर्ष 2017-18 में "आयुक्त निःशक्तजन कार्यालय का अधिष्ठान" योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1487/स.क./लेखा-बजट(03)/2017-18 दिनांक 22.07.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-15 के अन्तर्गत "आयुक्त निःशक्तजन कार्यालय का अधिष्ठान" हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश दिनांक 20.04.2017 के द्वारा ₹5.58 लाख एवं शासनादेश दिनांक 21.06.2017 द्वारा ₹1.83 लाख, इस प्रकार कुल ₹7.41 लाख की धनराशि पूर्व में अवमुक्त की गयी थी तथा वर्तमान में संलग्न एलोटमेन्ट आई.डी.संख्या-SI.707/5062 दिनांक 24.11.17 के द्वारा ₹11.90 लाख (रुपये ग्यारह लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. प्रश्नगत धनराशि का व्यय करते समय वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या:-610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
3. उक्त धनराशि केवल स्वीकृत मदों पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदों में न किया जाए।
4. स्वीकृत मदों में आवंटित धनराशि का उपयोग, यदि किसी अन्य मद में करना आवश्यक हो, तो व्यय/उपभोग करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार शासन अथवा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
5. आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के सम्पूर्ण लेखाशीर्षकों यथा मुख्य/लघु/उप/विस्तृत शीर्षक (मानक मद) तथा तत्सम्बन्धी अनुदान संख्या आदि का स्पष्ट उल्लेख बिलों में किया जाय, ताकि महालेखाकार से मिलान में असुविधा न हो।
6. स्वीकृति के संलग्नक के अनुसार आवंटित धनराशि को समय से उपयोग करने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों/सम्बन्धितों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय तथा आवंटित धनराशि के उपयोग आदि सूचना यथासमय शासन को प्रेषित किया जाय।
7. संलग्नक में वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त करते हुए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराये।

8. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियमवाली), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम) आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
  9. निर्गत की जा रही धनराशि के उपयोग में मितव्ययता की नितान्त आवश्यकता है। अतः धनराशि उपयोग/व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
  10. बी0एम0-08 पर संकलित मासिक व्यय की सूचनाएँ नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
  11. अधिष्ठान सम्बन्धी अन्य अवचनबद्ध मदों की धनराशि को आहरण-वितरण अधिकारियों को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करा दी जाय कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किशतों में वास्तविक व्यय, आवश्यकता के आधार पर ही किया जाय तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय, और न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जाय।
  12. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-15 के अंतर्गत संलग्न एलोटमेन्ट आई.डी. में उल्लिखित लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण, 101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, 11-विकलांगजन अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जाएगा।
  13. यह आदेश वित्त विभाग के पत्र शासनादेश संख्या:-610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्न-यथोक्त।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)  
सचिव।

संख्या: -133/11(1)/XVII-4/2017-10(19)/2009, तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
3. एन.आई.सी. उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
4. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(मनोज चन्द्रन)  
अपर सचिव।

- 1: लेखा शीर्षक 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 - समाज कल्याण
- 101 - विकलांग व्यक्तियों का कल्याण
- 11 - विकलांग जन अधिनियम 1995 के क्रियान्वन हेतु कार्यक्रम
- 00 - विकलांग जन अधिनियम 1995 के क्रियान्वन हेतु कार्यक्रम

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	272000	272000	544000
02 - मजदूरी	10000	20000	30000
03 - महंगाई भत्ता	17000	16000	33000
04 - यात्रा व्यय	3000	7000	10000
06 - अन्य भत्ते	13000	25000	38000
07 - मानदेय	2000	3000	5000
08 - कार्यालय व्यय	10000	20000	30000
09 - विद्युत देय	10000	20000	30000
10 - जलकर / जल प्रभार	3000	7000	10000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	10000	20000	30000
13 - टेलीफोन पर व्यय	20000	40000	60000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट	33000	67000	100000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	150000	300000	450000
17 - किराया, उपशल्क और कर-स्व	83000	167000	250000
18 - प्रकाशन	17000	33000	50000
19 - विज्ञापन, विक्री और विख्यापन	10000	20000	30000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	3000	7000	10000
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण औ	10000	20000	30000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपुर्ति	17000	33000	50000
42 - अन्य व्यय	14000	27000	41000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	17000	33000	50000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	17000	33000	50000
	741000	1190000	1931000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

1190000

(महेन्द्र सिंह नेगी)  
अनुभाग अधिकारी  
समाज कल्याण अनुभाग-04